देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 25.09.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :—

- राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 21 सितम्बर को आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में नकल के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई।
- केंद्र सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आज से उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे शुरु करगा; सर्वे के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण की समग्र रणनीति तैयार की जाएगी।
- प्रदेश में आज से 4 अक्टूबर तक शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा।

<u>एसआईटी जांच</u>

राज्य सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 21 सितम्बर को आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में नकल के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल— एसआईटी गठित की है।

एसआईटी की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक ग्रामीण देहरादून जया बलूनी करेंगी। दल में क्षेत्राधिकारी देहरादून अंकित कंडारी, निरीक्षक एलआईयू देहरादून लक्ष्मण सिंह नेगी, थानाध्यक्ष रायपुर गिरीश नेगी और उपनिरीक्षक साइबर पुलिस स्टेशन राजेश ध्यानी शामिल हैं।

यह दल पूरे प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों और तथ्यों की जांच करेगा और एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।

<u>मंजूरी</u>

केंद्र सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। यह केंद्र, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्थापित किया जाएगा।

इसकी स्थापना से राज्य की स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन क्षमता मजबूत होगी और आपात स्थितियों में समयबद्ध प्रतिक्रिया व बेहतर समन्वय संभव हो सकेगा। इसके संचालन के लिए वरिष्ठ सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाहकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाहकार, डेटा विश्लेषक, हब इंजीनियर और डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित नौ संविदा पद स्वीकृत किए गए हैं।

इस केंद्र के लिए धनराशि वर्ष 2026 तक उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार से संविदा पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा तोहफा दिया है, जिससे स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन और मजबूत होगा।

धनराशि स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं और आपदा राहत कार्यों के लिए 28 करोड़ 76 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

इसके तहत मानसून आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनःनिर्माण के लिए पिथौरागढ़ को 15 करोड़ तथा चमोली जिले के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृति दी गई है।

वहीं, उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में ग्राम पंचायत ओडाठा के बामसू गांव में महासू देवता स्थल पर सौंदर्यीकरण और सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए 99 लाख तथा महासू देवता मंदिर ठडियार में सौंदर्यीकरण और शौचालय निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र के मदकोट गांव में शिव मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 27 लाख और चमोली जिले के बद्रीनाथ क्षेत्र में माता अनसूया मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए भी डेढ़ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

वर्चुअल शुभारम्भ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट के प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल कक्षागृह का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर एक निजी बैंक के साथ 24 विद्यालयों के डिजिटलाइजेशन और और एक निजी कंपनी के साथ पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की कई प्रमुख कंपनियां सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में योगदान दे रही हैं। उन्होंने बताया कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन, 2023 में प्रदेश को तीन दशमलव पांच–छह लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं।

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को लापता बच्चों का पता लगाने और इससे संबंधित मामलों की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने निर्देश दिया कि प्रत्येक राज्य को पोर्टल के माध्यम से गुमशुदगी की शिकायतों और सूचना के प्रसार के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए।

आदेश

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में न्यायिक कार्यवाही को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्द्र ने निर्देश दिए हैं कि नवंबर 2025 के अंत तक यदि किसी पक्षकार या अधिवक्ता की बादल फटने, भूस्खलन या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण आवाजाही बाधित होने से समय पर न्यायालय में उपस्थिति नहीं हो पाती है, तो उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट प्रक्रिया

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से उत्तराखंड में पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए गठित टीमें उत्तरकाशी और चमोली पहुंच चुकी हैं और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर आज से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे शुरू करेंगी।

सचिव आपदा प्रबंधन, विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस वर्ष अतिवृष्टि, भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़ से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। अब तक 135 लोगों की मौत हुई है, जबकि 90 लोग लापता हैं। सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, कृषि भूमि और भवनों सहित बुनियादी ढांचे को भी गंभीर क्षति पहुंची है।

आपदा के बाद की आवश्यकताओं के आकलन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राज्य और जिला स्तर पर विशेषज्ञों को शामिल कर चार टीमें बनाई गई हैं, जो अलग–अलग जिलों में सर्वे करेंगी। इन दलों का उद्देश्य आपदा से हुई क्षति का आकलन कर पुनर्वास और पुनर्निर्माण की समग्र रणनीति तैयार करना है।

यह रिपोर्ट 'बिल्ड बैक बेटर' सिद्धांत पर आधारित होगी और इसमें अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक जरूरतों के साथ ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण और पर्यावरणीय पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। तैयार रिपोर्ट राज्य सरकार, गृह मंत्रालय को भेजेगी।

शहीद सम्मान यात्रा

प्रदेश में आज से 4 अक्टूबर तक शहीद सम्मान यात्रा के दूसरे चरण का आयोजन होगा। यात्रा का पहला चरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शहीद नायक नरेश कुमार के आवास से शुरू करेंगे। इस दौरान शहीद के आंगन की मिट्टी कलश में एकत्र कर यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा, जो शहीद के घर से शौर्य स्थल चीड़बाग तक जाएगी।

दूसरे चरण में 4 अक्टूबर को शौर्य स्थल चीड़बाग से शहीदों के आंगन की मिट्टी वाले कलशों को शहीद यात्रा रथ के माध्यम से लैंसडाउन रवाना किया जाएगा।

समीक्षा बैठक

हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने विकास भवन में नीति आयोग के आकांक्षी विकासखण्ड कार्यक्रम के अंतर्गत जल निकाय पुनर्जीवन कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में बताया गया कि कुल 50 कार्यों में से 40 पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनकी जानकारी अभी तक ''अवनि ग्रामीण ऐप'' पर अपलोड नहीं की गई है। इस लापरवाही पर मुख्य विकास अधिकारी ने गहरा असंतोष जताते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई।

उन्होंने सभी अद्यतन सूचनाएं एवं जल निकायों की पहले और बाद की तस्वीरें तत्काल पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि निर्धारित समय पर कार्य पूरे न करने की स्थिति में संबंधित विभागों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

विकसित राज्य

आजादी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के संकल्प के तहत 'विकसित भारत राज्य अभियान' के अंतर्गत 'विकसित उत्तराखण्ड विजन 2047' तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार इस विजन डॉक्यूमेंट को आम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने के लिए नागरिकों, शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा समुदाय आधारित संगठनों से सुझाव आमंत्रित कर रही है। प्राप्त सुझावों को दस्तावेज में उचित रूप से सम्मिलित किया जाएगा, जिससे विजन 2047 के प्रभावी क्रियान्वयन का सशक्त आधार तैयार हो सके।

इस संबंध में प्रमुख सचिव, नियोजन ने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वे 20 अक्टूबर तक अपने सुझाव वेबसाइट के माध्यम से भेजें। इच्छुक नागरिक क्यूआर कोड स्कैन करके भी सुझाव भेज सकते हैं।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर––

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रकरण को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है– पेपर लीक की एसआईटी जांच। नवोदय टाइम्स लिखता है– रिटायर्ड जज के सुपरविजन में होगी एसआईटी जांच। दैनिक जागरण लिखता है – यूकेएसएसएससी भर्ती परीक्षा की शुचिता को सरकार ने उठाया कदम, एक माह में शासन को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मेडिकल कॉलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर में सीटें बढ़ाए जाने की खबर को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। इस खबर पर अमर उजाला लिखता है – मेडिकल में स्नातक व पीजी की 10 हजार 23 सीटें बढ़ेंगी, छात्रों को मिलेंगे ज्यादा अवसर। दैनिक जागरण लिखता है – एबीबीबीएस की 5 हजार 23 सीटें बढ़ेंगी।

उत्तराखंड में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को केंद्र ने मंजूरी दी है। इस खबर पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है– राज्य में बनेगा हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। अमर उजाला लिखता है– केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, आपदा के समय स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत।